Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069(Print), Impact Factor: 7.650, Volume 11, No. 03, July-September, 2025, pp. 41-53

नागौर जिले में कृषि आधारित ग्रामीण औद्योगिकीकरणः सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

विजय अरोड़ा[1]*, डॉ. रजनीकांत त्रिवेदी[2]

[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
[2]सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: vijaininad1005@gmail.com

***Citation**: अरोड़ाविजय, & त्रिवेदीरजनीकांत. (2025). नागौर जिले में कृषि आधारित ग्रामीण औद्योगिकीकरणः सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावनाएँ. Journal of Commerce, Economics & Computer Science, 11(03), 41–53. https://doi.org/10.62823/jcecs/11.03.7824*

सार

नागौर जिला राजस्थान का एक अर्ध–शुष्क और कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण आबादी की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। पारंपरिक कृषि प्रणाली की सीमाओं, जलवायु असंतुलन और बेरोजगारी की चुनौतियों के बीच कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहे हैं। प्रस्तुत शोध लेख में नागौर जिले में कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों की वर्तमान स्थिति, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, विपणन व्यवस्था, तकनीकी नवाचार, सरकारी योजनाओं की भूमिका और प्रमुख बाधाओं का बहुआयामी विश्लेषण किया गया है। लेख में यह पाया गया कि मसाला प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद, जैविक खाद निर्माण, दाल मिल तथा तेल इकाइयाँ जिले में सबसे अधिक क्रियाशील हैं। ये उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार सृजन में सहायक हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, युवा उद्यमिता और ग्रामीण टिकाऊ अर्थव्यवस्था के वाहक भी हैं। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, विपणन बाधाएँ और योजनाओं की सीमित पहुँच इन उद्योगों के समुचित विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। शोध के निष्कर्ष स्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, डिजिटल विपणन, महिला एवं युवा केंद्रित प्रशिक्षण, और क्षेत्रीय ब्रांडिंग के माध्यम से नागौर को कृषि आधारित ग्रामीण औद्योगिकीकरण का आदर्श मॉडल बनाया जा सकता है।

शब्दकोशः *नागौर, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, विपणन, योजनाएँ, MSME.*

प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, लेकिन आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक असंतुलन के दौर में कृषि अकेले ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर और समृद्ध नहीं बना सकती। ऐसे में कृ षि से जुड़ी हुई औद्योगिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास की एक आवश्यक शर्त बन गई हैं।

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

कृषि आधारित उद्योगों की अवधारणा केवल मूल्यवर्धन (Value Addition) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन जैसे आयामों को भी छूती है। जब कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और विपणन होता है, तो न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की विविधता भी सुनिश्चित होती है।

राजस्थान का नागौर जिला, जो ऐतिहासिक रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित रहा है, कृषि आधारित औद्योगिकीकरण की दृष्टि से विशेष संभावनाओं से युक्त है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी और जनजीवन की संरचना ऐसी है कि यह क्षेत्र मसालों, दलहनों, जैविक खाद, दूध उत्पादों तथा पशु–आधारित उत्पादों के लघु उद्योगों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

इसके बावजूद, नागौर में इन उद्योगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और जो इकाइयाँ संचालित हैं, वे भी तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत चुनौतियों से जूझ रही हैं। यह स्थिति न केवल स्थानीय संसाधनों के अपव्यय की ओर संकेत करती है, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं के शहरों की ओर पलायन और कृषि पर बढ़ते बोझ को भी रेखांकित करती है।

इस लेख का उद्देश्य है कि नागौर जिले में कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थिति, प्रभाव और बाधाओं का गहन अध्ययन किया जाए और उनके आधार पर ठोस सुझाव दिए जाएँ जो नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए उपयोगी सिद्ध हों।

अध्ययन की पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं नागौर जिले का सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य

पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएँ आरंभ की गई हैं जैसे कि.

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) आदि।

इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार सृजन और उत्पाद विविधता संभव हो सके। नागौर जिले के लिए यह और भी आवश्यक है क्योंकि.

- जिले में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि सीमित है
- सिंचाई की निर्भरता वर्षा पर अधिक है
- बेरोजगारी और पलायन एक स्थायी चुनौती बन चुके हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नागौर जिले की कुल आबादी में लगभग 83% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनमें से 70% से अधिक कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। यदि इन समुदायों को स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकल्प प्रदान किए जाएँ, तो न केवल उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और स्थायी रोजगार भी प्राप्त हो सकता है।

अध्ययन की आवश्यकता

- क्षेत्रीय विषमताओं को कम करनादृ राज्य के अन्य जिलों की तुलना में नागौर में कृषि आधारित उद्योगों का विकास धीमा है।

- कृषि पर निर्भरता में विविधता लानादृ ग्रामीण आय के एकमात्र स्रोत के रूप में कृषि को कम कर विकल्प खड़ा करना आवश्यक है।
- महिला और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देना – SHG और FPO जैसे माध्यमों से ग्रामीण महिलाएँ उद्योगों में भागीदारी कर सकती हैं।
- स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग– नागौर के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे जीरा, मैथी, मूँग, सरसों आदि का स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन जरूरी है।
- विकेन्द्रीकृत औद्योगिक विकासदृ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से नगरीकरण पर दबाव कम होगा।

इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है ताकि नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका, प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावनाओं का वैज्ञानिक एवं साक्ष्य–आधारित मूल्यांकन किया जा सके।

नागौर जिले का सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य

नागौर जिला राजस्थान राज्य का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है जो मरुस्थलीय जलवायु, सीमित जल संसाधनों, तथा कृषि और पशुपालन आधारित ग्रामीण जीवनशैली के लिए जाना जाता है। जिले की जनसंख्या का लगभग 83ः हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है।

- **भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थितियाँ**
  - स्थानः नागौर जिला पश्चिमी राजस्थान के केंद्र में स्थित है, जो पूर्व में अजमेर, उत्तर में बीकानेर व चूरू, और दक्षिण में जोधपुर व पाली जिलों से घिरा हुआ है।
  - जलवायुः यहाँ का मौसम अर्ध–शुष्क (semi-arid) है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 350–400 मिमी. है।
  - भूमिः यहाँ की मिट्टी दोमट और रेतीली है, जिसमें दलहन व तिलहन की खेती विशेष रूप से होती है।
- **जनसांख्यिकीय विवरण (तालिका 1)**

विवरण	आँकड़े (2021)
कुल जनसंख्या	~37 लाख
ग्रामीण जनसंख्या	~30ण्7 लाख (83%)
साक्षरता दर	~64%
कार्यशील जनसंख्या	~45% कृषि व पशुपालन में
औसत भूमि जोत	ॅ1ण्8 हेक्टेयर

स्रोत: rajasthan.census.gov.in

- **आर्थिक गतिविधियाँ**
  - कृषिरू जीरा, मैथी, मूँग, मोठ, चना, सरसों, गेहूँ, बाजरा आदि।
  - पशुपालनरू दूध, मावा, घी तथा ऊन के उत्पादन में जिले की बड़ी भूमिका है।
  - बाजार केंद्ररू नागौर, डीडवाना, मेड़ता सिटी, कुचामन आदि प्रमुख बाजार हैं।

जिला नागौर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से औसत से नीचे है, किंतु सामाजिक श्रमबल और कृषि–पशुपालन में अनुभव ने इस क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। यही वह पृष्ठभूमि है जहाँ कृषि आधारित लघु उद्योग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों की अवधारणा

परिभाषा एवं स्वरूप

कृषि आधारित उद्योग वे इकाइयाँ होती हैं जो प्राथमिक कृषि उत्पादों को संसाधित कर उनका मूल्यवर्धन करती हैं। उदाहरण के लिए मसाले पीसने, दाल मिल, तेल मिल, दूध प्रसंस्करण, जैविक खाद उत्पादन, पैकेजिंग, आदि।

ये इकाइयाँ मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग ;डैडम्द्ध श्रेणी में आती हैं और इनके लिए निवेश, तकनीकी दक्षता तथा संसाधनों की आवश्यकता न्यूनतम होती है, जिससे ये ग्रामीण स्तर पर स्थापित और संचालित की जा सकती हैं।

विशेषताएँ

- स्थानीय कच्चे माल का उपयोग
- श्रम–प्रधानता ;स्इवनत पदजमदेपअमद्ध
- सीमित तकनीकी आवश्यकता
- कम पूँजी निवेश
- स्थानीय बाजार या घरेलू उपभोग हेतु उत्पादन

वर्गीकरण

- प्रसंस्करण इकाइयाँ – मसाला उद्योग, दाल मिल, खाद्य तेल इकाइयाँ
- डेयरी एवं पशु–आधारित उद्योग – दूध, घी, मावा, चमड़ा
- जैविक एवं पर्यावरणीय उत्पाद – वर्मी कम्पोस्ट, हर्बल उत्पाद
- हैंडमेड / पैकेजिंग इकाइयाँ – कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन

भूमिका और महत्त्व

- कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी
- ग्रामीण रोजगार में वृद्धि
- महिला सशक्तिकरण के अवसर
- स्थानीय आय में बढ़ोत्तरी
- स्थायी विकास की दिशा में कदम

नागौर जैसे जिले में जहाँ कृषि की सीमाएँ स्पष्ट हैं, वहाँ कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग नए अवसरों का द्वार खोलते हैं और इन्हें संस्थागत समर्थन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा विपणन नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता है

नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योग

नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों की उपस्थिति पारंपरिक रूप से मौजूद रही है, लेकिन यह अब तक मुख्यतः लघु, अनौपचारिक और तकनीकी रूप से पिछड़े स्वरूप में विकसित हुई है। हालाँकि पिछले एक दशक में स्थानीय उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और सरकारी योजनाओं के माध्यम से इसमें थोड़ी वृद्धि अवश्य हुई है।

प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार (तालिका 2)

उद्योग का प्रकार	अनुमानित इकाइयाँ	प्रमुख उत्पाद
मसाला प्रसंस्करण	~240	जीरा, मैथी, धनिया
तेल मिल	~190	सरसों, मूँगफली तेल
डेयरी उद्योग	~140	दूध, मावा, घी, पनीर
दाल मिल	~85	चना, मूँग, मोठ
जैविक खाद इकाइयाँ	~60	वर्मी कम्पोस्ट, बायोफर्टिलाइज़र
पशु–आधारित उत्पाद इकाइयाँ	~30	चमड़ा, हड्डी, सींग

इनमें से अधिकांश इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर संचालित होती हैं और पारिवारिक उद्यम के रूप में कार्य करती हैं।

भौगोलिक वितरण

- डीडवाना, कुचामन, नागौर शहरः मसाला और दाल मिल
- मेड़ता, परबतसरः जैविक खाद और दूध उत्पादन
- मूण्डवा, खींवसरः पशुपालन आधारित लघु उद्योग

प्रमुख प्रवृत्तियाँ

- MSME रजिस्ट्रेशन में वृद्धि (2020–2024 के बीच ~23% वृद्धिद्ध
- महिला स्व–सहायता समूहों की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन
- जिला उद्योग केंद्र (DIC), KVIC व कृषि विपणन मंडी की भागीदारी बढ़ी है

प्रमुख चुनौतियाँ

- वित्तीय संस्थानों से सीमित ऋण सुविधा
- आधुनिक तकनीकों का अभाव
- उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग में पिछड़ापन
- विपणन की पहुँच केवल स्थानीय बाजार तक सीमित

ग्रामीण रोजगार, आय और महिला भागीदारी

कृषि आधारित उद्योग नागौर जिले में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत हैं। ये उद्योग ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, जिससे स्थानीय जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

तालिका 3: नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार ;2010.2023द्ध

वर्ष	प्रत्यक्ष रोजगार (हजार में)	अप्रत्यक्ष रोजगार (हजार में)	कुल रोजगार (हजार में)	कुल रोजगार वृद्धि दर (%)
2010	15	10	25	-
2013	18	12	30	20.00%
2016	22	15	37	23.33%
2019	27	18	45	21.62%
2023	32	22	54	20.00%

स्रोतः आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

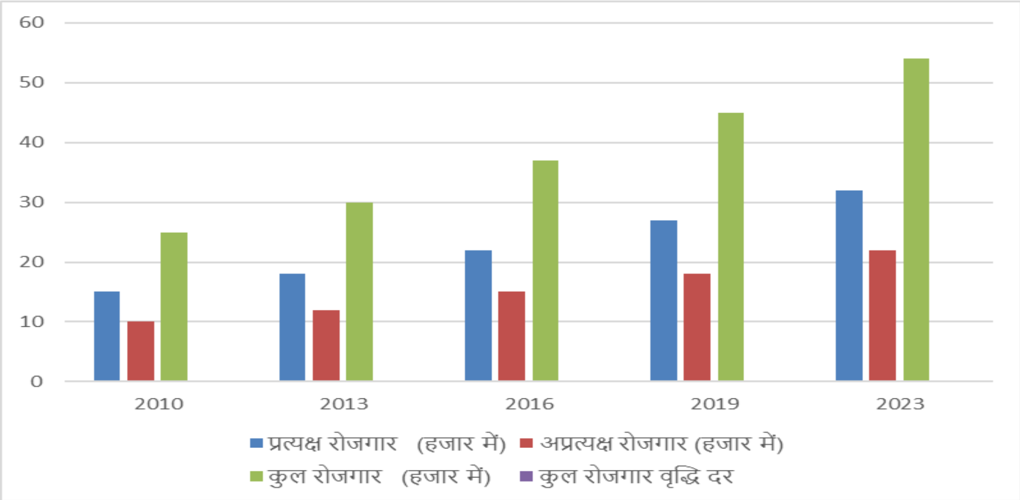

ग्राफ 1: नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार ;2010.2023द्ध

तालिका एवं ग्राफ के अनुसार, 2010 से 2023 के बीच नागौर जिले के कृषि आधारित उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है। 2023 में कुल 54,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए, जिनमें से 32,000 प्रत्यक्ष और 22,000 अप्रत्यक्ष रोजगार थे। यह स्पष्ट करता है कि कृषि आधारित उद्योग जिले में रोजगार सृजन का एक प्रमुख साधन हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बल मिलता है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

- **औसत रोजगार** (2010–2023)

श्रेणी	औसत रोजगार (हजार में)
प्रत्यक्ष रोजगार	22.8
अप्रत्यक्ष रोजगार	15.4
कुल रोजगार	38.2

इसका अर्थ है कि औसतन 38,200 लोगों को हर वर्ष रोजगार मिल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़ी संख्या है।

- **कुल रोजगार में वृद्धि**
  - 2010– 25 हजार
  - 2023– 54 हजार
  - कुल वृद्धि = 29 हजार (116% वृद्धि)

  कुल रोजगार 13 वर्षों में दोगुना से अधिक हो चुका है।

- **वर्षवार वृद्धि दर** (Growth Rate %)
  - सभी वर्षों में 20% या उससे अधिक की वृद्धि दर रही।
  - यह दर्शाता है कि कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार सृजन की गति स्थिर, प्रभावी और विश्वसनीय है।

- **सहसंबंध विश्लेषणरू**
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बीच च्मंतेवद सहसंबंध = +0.999

यह दर्शाता है कि जैसे–जैसे उद्योगों में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ता है, वैसे ही सप्लाई चेन, सेवाओं, ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ते हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि कृषि आधारित उद्योगों से रोजगार की मात्रा में निरंतर और स्थायी वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही स्तरों पर रोजगार सृजन में इनका योगदान महत्वपूर्ण है, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास, स्थानीय आजीविका और सामाजिक स्थायित्व को मजबूती मिलती है।

कृषि आधारित उद्योगों ने नागौर जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण पलायन की समस्या में भी कमी आती है। इसके अलावा, कृषि आधारित उद्योगों में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है।

तालिका 4ः नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार वितरण ;2023.24द्ध

उद्योग	कुल रोजगार (लाख)	महिलाओं का योगदान (%)	ग्रामीण श्रमिक (%)
खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)	0.5	35%	80%
तिलहन उद्योग (Oilseeds Industry)	0.35	30%	85%
डेयरी उद्योग (Dairy Industry)	0.4	40%	90%
आटा मिलिंग (Flour Milling)	0.25	25%	75%
मसाला उद्योग (Spice Industry)	0.15	20%	70%

स्रोतः आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

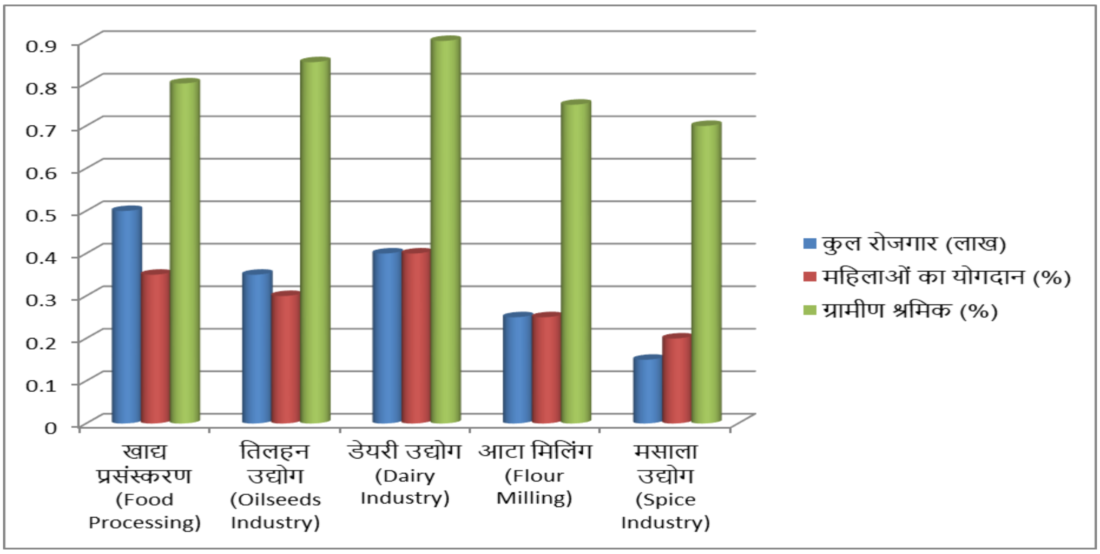

ग्राफ 2ः नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार वितरण (2023-24)

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार का वितरण ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के लिए श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार स्रोत के रूप में उभर कर आया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

- कुल रोजगार में योगदान (सभी उद्योग)

  कुल रोजगार = 0.50 + 0.35 + 0.40 + 0.25 + 0.15 = 1.65 लाख

  - केवल पाँच उद्योगों में ही 1ण्65 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

- औसत रोजगार प्रति उद्योग

औसत = 1.65/5 = 0.33 लाख (या 33,000) प्रति उद्योग

  - प्रत्येक उद्योग औसतन 33,000 लोगों को रोजगार दे रहा है।

- महिलाओं का औसत योगदानरू

  {35 + 30 + 40 + 25 + 20}/{5} = 150/5 = {30%}

  - हर तीसरा कर्मचारी महिला है, जो लैंगिक भागीदारी का संकेत है।

- ग्रामीण श्रमिकों का औसत योगदानः

  {80 + 85 + 90 + 75 + 70}/{5} = 400/5 = {80%}

  - हर 10 में से 8 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है किः

- कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार की मात्रा बहुत अधिक है. औसतन प्रति उद्योग 33,000 लोग कार्यरत हैं।
- 80% से अधिक श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये उद्योग ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ हैं।
- महिलाओं की भागीदारी 30% होना यह सिद्ध करता है कि कृषि आधारित उद्योग सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देते हैं।

अतः यह सांख्यिकीय रूप से सिद्ध होता है कि कृषि आधारित उद्योग न केवल उत्पादन, बल्कि रोजगार सृजन का भी सशक्त माध्यम हैं कृ विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए।

संयुक्त निष्कर्षरू कृषि आधारित उद्योगों का रोजगार पर प्रभाव

कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका न केवल आर्थिक विकास तक सीमित है, बल्कि वे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ग्रामीण और महिला श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2010 से 2023 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल रोजगार 25 हजार से बढ़कर 54 हजार हो गया, जो 116% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि हर अवधि में औसतन 20–23% के बीच रही है – जो एक स्थायी और स्थिर रोजगार प्रवृत्ति का संकेत है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों में 1ण्65 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है, जिनमें से औसतन 30% महिलाएँ हैं और 80% से अधिक श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि ये उद्योग केवल उत्पादन नहीं, बल्कि समावेशी रोजगार सृजन का केंद्र भी हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह भी सिद्ध हुआ किः

- औसतन प्रत्येक कृषि उद्योग में 33,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बीच लगभग पूर्ण सहसंबंध (r = +0.999) है, जो दर्शाता है कि जैसे–जैसे उद्योग बढ़ते हैं, सभी स्तरों पर रोजगार बढ़ता है।

उपरोक्त दोनों विश्लेषणों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि कृषि आधारित उद्योगरू

- रोजगार की मात्रा में निरंतर वृद्धि करते हैं,
- ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से सक्रिय बनाते हैं, और
- महिलाओं को कार्यबल में सहभागी बनाते हैं।

इसलिए कृषि आधारित औद्योगिकीकरण को केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि समाज और रोजगार की दृष्टि से भी एक रणनीतिक आवश्यकता माना जाना चाहिए।

विपणन, वितरण और तकनीकी नवाचार

कृषि आधारित उद्योगों की सफलता का निर्धारण केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विपणन रणनीति, दक्ष वितरण व्यवस्था, और तकनीकी उन्नयन की दिशा में भी प्रगति आवश्यक होती है। नागौर जिले में यह तीनों क्षेत्र अब भी विकास की प्राथमिक अवस्था में हैं।

- **विपणन की वर्तमान स्थिति**
  - स्थानीय मंडियाँः अधिकांश उत्पाद अब भी केवल तालुका/ब्लॉक स्तर की मंडियों में बेचे जाते हैं।
  - बिचौलियों पर निर्भरतारू उत्पादकों को औसत 10.20ः तक मूल्य हानि का सामना करना पड़ता है।
  - ब्रांडिंग और लेबलिंग का अभावः गुणवत्तायुक्त उत्पाद भी अनब्रांडेड रूप में कम कीमत पर बिकते हैं।

वितरण और आपूर्ति चौन

- अधिकतर इकाइयाँ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँच नहीं रखतीं।
- भंडारण एवं शीत–श्रृंखला ;बवसक बींपदद्ध की सुविधाओं की अत्यंत कमी है।
- उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री या ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ाव न्यूनतम है।

तकनीकी नवाचार की स्थिति (तालिका 5)

क्षेत्र	नवाचार की उपलब्धता	चुनौतियाँ
मसाला ग्राइंडिंग	मध्यम	मशीनों की गुणवत्ता और रख–रखाव में कमी
जैविक खाद उत्पादन	उच्च (SHG द्वारा)	प्रशिक्षण और गुणवत्ता परीक्षण की कमी
डेयरी प्रोसेसिंग	निम्न	बिजली आपूर्ति और उपकरणों की समस्या
पैकेजिंग	बहुत निम्न	ब्रांडिंग सामग्री और डिज़ाइन का अभाव

नवाचार के संभावित स्रोत

- राजस्थान स्टार्टअप मिशन और KVIC तकनीकी केंद्रों के साथ साझेदारी
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा प्रशिक्षण
- डिजिटल विपणन में युवाओं को जोड़ने की पहल

प्रमुख चुनौतियाँ और बाधाएँ

नागौर जिले में कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के मार्ग में कई बाधाएँ अब भी विद्यमान हैं। ये बाधाएँ केवल आर्थिक नहीं बल्कि संरचनात्मक, तकनीकी और सामाजिक भी हैं।

- वित्तीय चुनौतियाँ
  - बैंक और NBFC से ऋण प्राप्त करना कठिन
  - अनौपचारिक पूंजी पर निर्भरता
  - वर्किंग कैपिटल की कमी
- संस्थागत सीमाएँ
  - PMFME, MSME जैसी योजनाओं की जमीनी पहुँच कम
  - SHG और FPO की प्रशासनिक रुकावटें
  - उद्यमियों में सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव
- तकनीकी एवं मानव संसाधन
  - तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, खासकर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं में
  - अनुभवी प्रशिक्षकों की उपलब्धता कम
  - क्वालिटी कंट्रोल, लैब सुविधा और प्रमाणन प्रणाली का अभाव
- विपणन और लॉजिस्टिक्स
  - उत्पादों की दूरी तक पहुँचाने की व्यवस्था कमजोर
  - ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीमित संपर्क
  - विज्ञापन और प्रचार के साधनों की जानकारी नहीं
- सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोध
  - महिला उद्यमिता को परंपरागत सोच से बाधा
  - संयुक्त परिवारों में आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सीमित
  - युवाओं में स्थानीय स्तर पर उद्योग को करियर विकल्प के रूप में देखने की कमी

ये सभी बाधाएँ इस ओर इशारा करती हैं कि केवल नीति निर्माण ही नहीं, बल्कि नीतियों का ज़मीनी क्रियान्वयन, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण, और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

योजनाएँ, नीतियाँ और सरकारी प्रयास

कृषि आधारित लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। ये योजनाएँ मुख्यतः वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहयोग और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

- **प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएँ (तालिका 6)**

योजना／कार्यक्रम	उद्देश्य
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)	माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को वित्त और तकनीकी सहायता
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)	क्षेत्रीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना
आत्मनिर्भर भारत अभियान	स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को प्रोत्साहित करना
स्टार्टअप इंडिया	नवाचार आधारित ग्रामीण उद्यमिता को सहयोग
मुद्रा योजना (MUDRA)	सूक्ष्म उद्यमों के लिए बिना गारंटी ऋण सुविधा

- **राजस्थान सरकार की पहलें**
  - राजस्थान MSME नीति 2022: नए उद्योगों को स्टांप ड्यूटी छूट, बिजली सब्सिडी और क्लस्टर विकास की सुविधा।
  - राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन (RGAVP): SHG आधारित ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना।
  - राजस्थान कृषि विपणन नीतिरू ई–नाम प्लेटफॉर्म और मंडियों में पारदर्शिता।
- **नागौर जिले में योजनाओं की स्थिति (तालिका 7)**

योजना	लाभार्थी इकाइयाँ ;2021दृ24द्ध	प्रमुख अड़चनें
PMFME	130+	आवेदन प्रक्रिया जटिल
MUDRA _.k	1800+	क्रेडिट स्कोर आधारित अस्वीकृति
RGAVP (SHG)	~1000 महिला समूह	विपणन प्रशिक्षण की कमी
ODOP (मसाला क्लस्टर)	प्रस्तावित–कार्य प्रारंभिक	भूमि व लॉजिस्टिक्स की समस्या

स्रोतः आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

यह स्पष्ट है कि योजनाओं की घोषणा और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक खाई है जिसे प्रशिक्षण, जागरूकता और संस्थागत समन्वय के माध्यम से पाटा जा सकता है।

सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण

नागौर जिले में कृषि आधारित लघु उद्योगों का विकास केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक संरचना, लैंगिक भूमिका, ग्रामीण जीवन शैली, और सामुदायिक संबंधों पर भी परिलक्षित हो रहा है।

- आय और जीवन स्तर में सुधार
  - कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण किसानों को अधिक मूल्य दिलवा रहा है।
  - अनेक ग्रामीण परिवारों की मासिक आय ₹20,000 से ऊपर हो चुकी है।
  - परिवारों की भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय क्षमताएँ बढ़ी हैं।
- महिला सशक्तिकरण
  - स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ अब आर्थिक निर्णयों में भाग ले रही हैं।
  - पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं से आगे बढ़कर महिलाएँ उद्यमी बनी हैं।
  - SHG के ज़रिए महिला नेतृत्व में चलने वाली इकाइयाँ बढ़ रही हैं।

- युवाओं का स्थानीय स्थायित्व
  - उद्योगों में कार्यरत युवा अब पलायन की बजाय स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - गाँवों में तकनीकी प्रशिक्षण एवं नवाचार की माँग बढ़ी है।
- सामाजिक समावेशन
  - आर्थिक विकास के साथ—साथ विभिन्न जाति एवं वर्गों के बीच सामाजिक सहभागिता और सहनिर्भरता का वातावरण बना है।
  - महिला और युवाओं की भागीदारी ने सामाजिक संतुलन को नया रूप दिया है।

सुझाव और सुधारात्मक उपाय

निम्नलिखित उपायों के माध्यम से नागौर में कृषि आधारित उद्योगों को अधिक प्रभावी एवं स्थायी बनाया जा सकता हैरू

- वित्तीय सुधार
  - बैंक ऋण की प्रक्रिया सरल बनाई जाए।
  - ग्रामीण SHG और FPO के लिए सब्सिडी आधारित पूंजी सुविधा बढ़ाई जाए।
  - डिजिटल भुगतान और लघु बीमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जाए।
- प्रशिक्षण एवं नवाचार
  - कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और ITI संस्थानों को उद्योगोन्मुखी बनाया जाए।
  - मोबाइल वैन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हो।
  - SHG के माध्यम से "ट्रेन—द—ट्रेनर" मॉडल अपनाया जाए।
- विपणन और ब्रांडिंग
  - "नागौर उत्पाद" के तहत एक विशिष्ट ब्रांड स्थापित हो।
  - स्थानीय मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
  - उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और डिज़ाइन सहायता मिले।
- महिला एवं युवा उद्यमिता
  - महिला SHG को उत्पाद निर्माण से विपणन तक संपूर्ण श्रृंखला में भागीदारी मिले।
  - ग्रामीण युवाओं के लिए EDP (Entrepreneurship Development Programme) होस्ट किए जाएँ।
  - किशोरियों के लिए "ग्रामीण बिज़नेस क्लब" जैसी पहलें चलाई जाएँ।

निष्कर्ष

नागौर जिले में कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास न केवल क्षेत्रीय आर्थिक मजबूती का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक पुनर्गठन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण स्थायित्व की भी आधारशिला बनता जा रहा है।

हालाँकि संसाधनों की कमी, नीतियों के क्रियान्वयन की धीमी गति, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव और विपणन की सीमाएँ अभी भी बाधाएँ हैं, परंतु स्थानीय जनसांस्कृतिक क्षमता, सरकार की नीतियाँ और बढ़ती जागरूकता इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखती हैं।

यदि यह प्रयास जनसहभागिता, संस्थागत सहयोग और नवाचार पर आधारित हो, तो नागौर जैसे अर्ध–शुष्क जिले को "कृषि औद्योगिक क्षेत्रीय मॉडल" के रूप में विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय: PMFME योजना दस्तावेज़ (2021)
2. MSME Annual Report 2023–24, भारत सरकार
3. राजस्थान राज्य औद्योगिक नीति 2022
4. जिला उद्योग केंद्र, नागौरः वार्षिक प्रतिवेदन (2022–23)
5. कृषि विज्ञान केंद्र, नागौर – ग्रामीण प्रसंस्करण प्रशिक्षण रिपोर्ट
6. SHG फेडरेशन, नागौर – महिला समूह आँकड़े
7. योजना पत्रिका, ग्रामीण रोजगार विशेषांक (2023)
8. www.nagaur.rajasthan.gov.in – जिला सांख्यिकी रिपोर्ट
9. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, GOI
10. NITI Aayog Policy Briefs on Rural Enterprises (2022).

❑❑❑